भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 182

उत्तर देने की तारीख-01/12/2025

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन संबंधी आंकड़े

†182. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:
श्री नरेश गणपत म्हस्के:
श्रीमती भारती पारधी:
श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास विगत एक वर्ष के दौरान विद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) संबंधी सुधारों के कार्यान्वयन के संबंध में कोई आंकड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्र-वार विशेषकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के संदर्भ में ब्यौरे क्या हैं;
(ख) क्या बहु-विषयक शिक्षा और कौशल-आधारित शिक्षा हेतु पायलट कार्यक्रमों का छात्रों के शैक्षणिक और व्यावसायिक परिणामों पर उनके प्रभाव के लिए मूल्यांकन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार द्वारा विगत वर्ष के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत विशेषकर ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में शिक्षकों के प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम की पुनर्संरचना को सुकर बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(घ) सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ढांचे के अंतर्गत डिजिटल शिक्षण उपकरणों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) द्वारा संचालित व्यक्तिगत शिक्षा को एकीकृत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
(ङ.) सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों और शारीरिक रूप से निःशक्त छात्रो को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत शुरू की गई प्रशिक्षण पहलों से लाभान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क): राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) की घोषणा के बाद, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों, सीबीएसई, एनसीईआरटी, एनसीटीई, यूजीसी, एआईसीटीई आदि जैसे विभिन्न हितधारकों द्वारा कई प्रभावशाली सुधार और पहलें की गई हैं।

मूलभूत, प्रारंभिक और मध्य चरणों (क्रमशः कक्षा 3, 6 और 9) के अंत में विद्यार्थियों की क्षमताओं के विकास में आधारभूत प्रदर्शन को समझने के लिए दिनांक 04.12.2024 को महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित पूरे भारत में परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 का आयोजन किया गया। देश भर में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 781 जिलों के 74,229 से अधिक स्कूलों के 21.15 लाख से अधिक विद्यार्थियों और 2.70 लाख शिक्षकों ने सर्वेक्षण में भाग लिया। परख सर्वेक्षण में महाराष्ट्र शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक के रूप में उभरा है, जिसमें कक्षा 3, 6 और 9 में 123,000 से अधिक विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया गया है, जबकि मध्य प्रदेश से इन कक्षाओं में 1,38,526 से अधिक विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया गया है। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर के रिपोर्ट कार्ड https://dashboard.parakh.ncert.gov.in/en पर उपलब्ध हैं।

शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस (यूडाइज+) 2024-25 के अनुसार, भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली में प्रमुख शैक्षिक संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। इसमें विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के लगभग 14.72 लाख स्कूलों और मूलभूत से लेकर माध्यमिक स्तर तक के लगभग 24.7 करोड़ विद्यार्थियों के आंकड़े हैं। शिक्षकों की संख्या 98.07 लाख से बढ़कर 1.01 करोड़ हो गई, जिसमें कुल 54.82 लाख महिला शिक्षक हैं, जो अपेक्षाकृत अधिक लैंगिक-संतुलित कार्यबल को दर्शाता है। वर्ष 2024-25 में सभी स्तरों पर विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात में सुधार हुआ। यह अनुपात अब मूलभूत स्तर पर 10 है, प्रारंभिक स्तर पर 13, मध्य स्तर पर 17 और माध्यमिक स्तर पर 21 है। ये अनुपात एनईपी के 1:30 मानक से बेहतर हैं, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी पर अधिक ध्यान देने और बेहतर अधिगम परिणाम सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में प्रारंभिक (3.7% से 2.3% तक), मध्य (5.2% से 3.5% तक) और माध्यमिक स्तर (10.9% से 8.2% तक) में 2023-24 की तुलना में ड्रॉपआउट दर में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। वर्ष 2024-25 में सभी स्तरों पर विद्यार्थी प्रतिधारण में सुधार हुआ। मूलभूत स्तर 98.0 प्रतिशत से बढ़कर 98.9 प्रतिशत

हो गया। प्रारंभिक स्तर 85.4 प्रतिशत से बढ़कर 92.4 प्रतिशत हो गया। मध्य स्तर 78.0 प्रतिशत से बढ़कर 82.8 प्रतिशत हो गया। माध्यमिक स्तर 45.6 प्रतिशत से बढ़कर 47.2 प्रतिशत हो गया। शैक्षणिक वर्ष 2024–25 में मध्य और माध्यमिक स्तरों पर सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि दर्ज की गई। मध्य स्तर 89.5 प्रतिशत से बढ़कर 90.3 प्रतिशत हो गया। माध्यमिक स्तर 66.5 प्रतिशत से बढ़कर 68.5 प्रतिशत हो गया। यह वृद्धि शिक्षा तक बेहतर पहुंच और उच्चतर कक्षाओं में विद्यार्थियों की बढ़ी हुई भागीदारी को दर्शाती है।

महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात, लैंगिक समानता, ड्रॉपआउट दर में कमी, प्रतिधारण दर में वृद्धि, सकल नामांकन अनुपात आदि के मामले में काफी सुधार हुआ है, जो उच्चतर कक्षाओं में बेहतर पहुंच और उच्च भागीदारी को दर्शाता है।

उच्चतर शिक्षा में, वार्षिक वेब आधारित 'अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई) ' उच्चतर शिक्षा पर एक व्यापक डेटा स्रोत है। एआईएसएचई 2022-23 (अनंतिम) रिपोर्ट में एआईएसएचई 2021-22 की तुलना में विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय स्तर की संस्थाओं और कॉलेजों की संख्या क्रमशः 1168 से 1213 और 45473 से 46624 तक बढ़ गई है। उच्चतर शिक्षा में नामांकन वर्ष 2021 में 4.33 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 4.46 करोड़ हो गया है। वर्ष 2022-23 में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों का नामांकन 69.13 लाख है, जबकि वर्ष 2021-22 में यह संख्या 66.23 लाख थी। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का नामांकन वर्ष 2021-22 में 27.10 लाख से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 28.72 लाख हो गया है। कुल एसटीईएम नामांकन 99.76 लाख है। विगत वर्ष की तुलना में संकाय की संख्या भी 15.97 लाख से बढ़कर 16.64 लाख हो गई है। विगत वर्ष की तुलना में कुल मिलाकर जीईआर 28.4 से बढ़कर 29.5 हो गया है।

महाराष्ट्र में, एआईएसएचई 2022-23 (अनंतिम) के अनुसार, विश्वविद्यालय और कॉलेजों की कुल संख्या क्रमशः 78 और 5390 है। उच्चतर शिक्षा में नामांकन 48.59 लाख विद्यार्थियों तक पहुंच गया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नामांकन की संख्या क्रमशः 6.22 लाख और 2.32 लाख है। एसटीईएम में कुल नामांकन 10.93 लाख है। संकाय की संख्या बढ़कर 1.78 लाख हो गई। कुल मिलाकर जीईआर में 37.8 तक सुधार हुआ है, जबकि मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की कुल संख्या क्रमशः 78 और 2582 है। उच्चतर शिक्षा में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या 27.35 लाख है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति

के नामांकनों की संख्या क्रमशः 4.13 लाख और 3.17 लाख है। एसटीईएम में कुल नामांकन 6.44 लाख है। संकाय की संख्या बढ़कर 85,664 हो गई। कुल मिलाकर, जीईआर 28.3 है।

पहुंच और सुलभता में सुधार हेतु, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना शुरू की गई है। यह एक सरल डिजिटल प्रणाली के माध्यम से मेधावी विद्यार्थियों को बिना संपार्श्विक के शिक्षा ऋण प्राप्त करने में मदद करता है। वर्ष 2024-25 से वर्ष 2030-31 तक 7 लाख नए विद्यार्थियों के लिए ब्याज में 3 प्रतिशत की छूट प्रदान करने हेतु 3600 करोड़ रुपये के परिव्यय को अनुमोदन प्रदान किया गया है। अब तक लगभग 5 लाख शिक्षा ऋण आवेदन प्राप्त हुए हैं और लगभग 5000 करोड़ रुपये के 1.71 लाख ऋण वितरित किए गए हैं।

बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, बजट घोषणा 2025-26 के अनुसार, भारतीय भाषा पुस्तक योजना में अगले तीन वर्षों में 22 भारतीय भाषाओं में विभिन्न स्कूल और उच्चतर शिक्षा विषयों में पाठ्यपुस्तकें डिजिटल प्रारूप में उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है।

सरकार ने उच्चतर शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ाने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की है। इसने वर्ष 2023 से 2028 के दौरान सरकारी सहायता और सार्वजनिक और निजी भागीदारों के योगदान के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बनाई है।

"भारत में एआई बनाएं और एआई को भारत के लिए काम पर लगाएं" की संकल्पना को साकार करने के लिए, वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 की अवधि में स्वास्थ्य, कृषि और सतत शहरों में ₹990 करोड़ के परिव्यय के साथ तीन एआई उत्कृष्टता केंद्र अनुमोदित किए गए हैं। 500 करोड़ रुपए के साथ शिक्षा में एआई के एक नए उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की गई है।

उच्चतर शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों के परिणामस्वरूप अधिक से अधिक उच्चतर शिक्षा संस्थानों को अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में स्थान दिया जा रहा है। क्यूएस 2026 में, 54 भारतीय एचईआई/विश्वविद्यालयों को स्थान दिया गया है जबकि क्यूएस 2025 में यह संख्या 46 है। क्यूएस 2026 में शीर्ष 500 में 10 भारतीय एचईआई हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, एशिया 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व 294 विश्वविद्यालयों के साथ दूसरा है, जो वर्ष 2025 में 163 से ऊपर है और शीर्ष 100 में 7 संस्थान हैं। 137 नए भारतीय संस्थान पहली बार रैंकिंग में शामिल हुए हैं, जो भारतीय उच्चतर शिक्षा के तीव्र विस्तार और बढ़ती वैश्विक दृश्यता को दर्शाता है। क्यूएस सब्जेक्ट रैंकिंग 2025 में 79 भारतीय एचईआई शामिल हैं, जो विगत

वर्ष के 69 की तुलना में 10 अधिक हैं, जो 14% की वृद्धि को दर्शाते हैं। 533 प्रविष्टियों में भारतीय संस्थानों का प्रतिनिधित्व किया गया, जो पिछले संस्करण की 424 प्रविष्टियों से 25.7% अधिक है।

भारत ने बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई है, जिसमें वर्ष 2023-24 में 92,168 पेटेंट आवेदन दर्ज किए गए हैं - जो वर्ष 2022-23 के बाद से 11.29% से अधिक की वृद्धि है। इस वृद्धि का एक मुख्य कारण शैक्षणिक संस्थानों का योगदान रहा है। घरेलू शैक्षणिक संस्थानों द्वारा पेटेंट फाइलिंग वर्ष 2021-22 में 7405 से तीन गुना से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 23,306 हो गई है। भारत में नवाचार को बढ़ावा देने में शैक्षिक संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

अनुसंधान और नवाचार पर एनईपी के फोकस ने वैश्विक नवाचार सूचकांक (जीआईआई) में भारत की रैंकिंग को वर्ष 2020 में 48वें स्थान से वर्तमान वर्ष 2025 में 38वें स्थान पर पहुंचा दिया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भारतीय उच्चतर शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए निरंतर प्रयासों ने प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालयों को भारतीय शिक्षा परिदृश्य में प्रवेश करने में सक्षम बनाया है। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इटली जैसे देशों के 12 विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों को भारत में ऑफशोर कैंपस स्थापित करने के लिए आशय पत्र (एलओआई) जारी किए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के बेंगलुरु परिसर हेतु एलओआई के लिए आगे का आवेदन अनुमोदित किया गया है। डीकिन विश्वविद्यालय और वूलोंगॉन्ग विश्वविद्यालय गिफ्ट सिटी, गांधीनगर के माध्यम से भारत में प्रवेश कर चुके हैं। साथ ही, यूके से कोवेंट्री यूनिवर्सिटी और क्वीन्स यूनिवर्सिटी बेलफ़ास्ट को हाल ही में गिफ्ट सिटी में अपने शाखा परिसर स्थापित करने की अनुमति दी गई है। आईआईएम अहमदाबाद (आईआईएम ए) और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) सरकार ने दुबई इंटरनेशनल एकेडमिक सिटी (डीआईएसी) में आईआईएमए दुबई कैंपस की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आईआईएम ए ने दिनांक 11.09.2025 को अपने परिसर का उद्घाटन किया।

(ख): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग केंद्र प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना को कार्यान्वित कर रहा है, जो अन्य बातों के साथ-साथ कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए कौशल परिचय और कक्षा 9 से 12 के लिए एनएसक्यूएफ-अनुरूप कौशल पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करते हुए व्यवसायपरक शिक्षा को बढ़ावा देता है। माध्यमिक स्तर पर, विद्यार्थी अतिरिक्त विषय के रूप में कौशल मॉड्यूल लेते हैं, जबकि वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर, कौशल पाठ्यक्रम वैकल्पिक विषयों के रूप में कार्य करते हैं। कुल 138

अनुमोदित जॉब रोल्स प्रदान किए जाते हैं, और प्रत्येक में संचार, स्व-प्रबंधन, आईसीटी, उद्यमिता और हरित कौशल को कवर करने वाला एक रोजगार कौशल मॉड्यूल शामिल है। विभाग स्कूलों में पीएमकेवीवाई 4.0 भी लागू कर रहा है, जिसमें 350 केंद्रीय विद्यालय कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। 21,700 से अधिक स्कूल अब नवाचार, उद्यमशीलता, आलोचनात्मक सोच और आईपी जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए स्कूल नवाचार परिषदों की मेजबानी करते हैं।

एनएसक्यूएफ के अनुरूप ये जॉब रोल्स आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और विनिर्माण जैसे प्रमुख क्षेत्रों को कवर करती हैं। विद्यार्थियों को आईटी क्षेत्र में जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, एआई सहायक, वेब डेवलपर तथा साइबर सुरक्षा सहयोगी जैसी भूमिकाओं में प्रशिक्षण दिया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित विकल्पों में सीसीटीवी तकनीशियन, ड्रोन सेवा तकनीशियन, सौर पीवी इंस्टॉलर और घरेलू उपकरण तकनीशियन शामिल हैं। विनिर्माण भूमिकाओं में ड्राफ्ट्समैन, सहायक राजमिस्त्री, निर्माण चित्रकार और ईंट राजमिस्त्री शामिल हैं। ये पेशकशें विद्यार्थियों को उद्योग-प्रासंगिक कौशल के बारे में शीघ्र जानकारी प्रदान करती हैं और भविष्य में रोजगार के लिए एक सुदृढ़ आधार बनाने में मदद करती हैं।

एआईसीटीई अपने तकनीकी कार्यक्रमों के साथ कौशल विकास और एकीकरण की दिशा में ठोस प्रयास कर रहा है। यह ऑनलाइन मोड में कौशल विकास पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए विभिन्न उद्योगों और संस्थानों के साथ सहकार्य कर रहा है जो नियमित पाठ्यक्रम में एकीकृत हैं। इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य विद्यार्थियों के व्यावहारिक कौशल को बढ़ाना और उन्हें अधिक रोजगारपरक बनाना है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के पास उपलब्ध आंकड़े तकनीकी शिक्षा के स्तर पर विद्यार्थी के प्लेसमेंट में वृद्धि की प्रवृत्ति का संकेत देते हैं। एआईसीटीई-अनुमोदित संस्थानों द्वारा स्व-प्रकटीकृत जानकारी के अनुसार, डिप्लोमा स्तर के विद्यार्थियों की संख्या वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1,80,866 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 1,91,801 हो गई। इसी तरह, अवर स्नातक स्तर पर, वर्ष 2023-24 में प्लेसमेंट 4,10,843 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 4,71,227 हो गया है।

(ग): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने केंद्र प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना के तहत निष्ठा - स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति हेतु राष्ट्रीय पहल नामक एक एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से प्रारंभिक स्तर पर अधिगम परिणामों में सुधार करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन भी शुरू किया है। निष्ठा "एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार" के लिए एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। निष्ठा ऑनलाइन का शुभारंभ अक्टूबर, 2020 में दीक्षा प्लेटफॉर्म का उपयोग करके किया गया था। वर्ष 2021-22

में माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के लिए निष्ठा प्रशिक्षण का विस्तार किया गया है। बाद में, निष्ठा ने प्रमुख प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु मूलभूत साक्षरता और संख्याज्ञान तथा प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) का भी विस्तार किया। अब तक 65 लाख से अधिक शिक्षक/स्कूल प्रमुख/प्रमुख प्रशिक्षक शामिल किए जा चुके हैं।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा-स्कूल शिक्षा (एनसीएफ-एसई) दिनांक 23.08.2023 को जारी की गई थी। एनसीएफ-एसई के तहत, पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप बनाया गया है, जिसमें मूलभूत से माध्यमिक स्तर तक स्कूली शिक्षा के 5+3+3+4 डिजाइन पर बल दिया गया है। एनसीएफ-एसई के तहत वर्ष 2024-25 के लिए कक्षा 3 और 8 की पाठ्यपुस्तकें जारी कर दी गई हैं। दिनांक 20.10.2022 को शुरू की गई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा - मूलभूत चरण (एनसीएफ-एफएस), 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए पहला एकीकृत फ्रेमवर्क है। इसके एक भाग के रूप में, जादुई पिटारा अधिगम सामग्री दिनांक 20.02.2023 को शुरू की गई थी। एनसीएफ-एफएस पर आधारित कक्षा 1 और 2 के लिए पाठ्यपुस्तकें, जो खेल-आधारित अधिगम पर केंद्रित हैं, दिनांक 05.07.2023 को जारी की गईं और 22 भाषाओं में उपलब्ध हैं। दिनांक 10.02.2024 को जादुई पिटारा का एक डिजिटल संस्करण शुरू किया गया था।

उच्चतर शिक्षा में, एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना अर्थात् मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (एमएमटीटीपी) 151 मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। इसका उद्देश्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों के संकाय की क्षमता और दक्षता को बढ़ाना है। इस उद्देश्य के लिए, विभिन्न क्षमता निर्माण कार्यक्रमों नामतः एनईपी अभिविन्यास व संवेदन कार्यक्रम, रिफ्रेशर कोर्स, संकाय प्रेरण कार्यक्रम, अल्पकालिक कार्यक्रम, एचईआई में सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य, व्यवहार्यता और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए क्षमता निर्माण, भावी नेतृत्व संवर्धन कार्यक्रम, डिजाइन एवं उद्यमिता संबंधी क्षमता निर्माण, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगताओं संबंधी क्षमता निर्माण, अकादमिक नेतृत्व कार्यक्रम, साइबर सुरक्षा संबंधी क्षमता निर्माण कार्यक्रम (संकाय के लिए), कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी क्षमता निर्माण कार्यक्रम (संकाय और शैक्षणिक नेताओं के लिए), एसटीईएम संबंधी क्षमता निर्माण कार्यक्रम (संकाय के लिए), प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण और एसटीईएम संकाय के लिए विज्ञान संप्रेषण संबंधी क्षमता निर्माण कार्यशाला की संकल्पना की गई है। अब तक इन केंद्रों द्वारा विभिन्न घटकों के तहत 4295 कार्यक्रम संचालित किए जा चुके हैं, जिससे 3.22 लाख संकाय लाभान्वित हुए हैं।

समकालीन उद्योग मांगों और तकनीकी प्रगति के अनुरूप पाठ्यक्रमों को प्रासंगिक बनाने के लिए, उच्चतर शिक्षा में विभिन्न पहलें/सुधार किए गए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय क्रेडिट फ़्रेमवर्क (एनसीआरएफ़); राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता फ़्रेमवर्क (एनएचईक्यूएफ़); अवर स्नातक कार्यक्रम हेतु पाठ्यक्रम एवं क्रेडिट फ़्रेमवर्क; तथा 'प्रोफेसर ऑफ़ प्रैक्टिस' संबंधी दिशा-निर्देश, जो एचईआई को उद्योग विशेषज्ञों के साथ कार्य करने में सक्षम बनाते हैं। कृषि, स्वास्थ्य और जैव-इलेक्ट्रॉनिक्स, बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं व बीमा (बीएफएसआई), ऊर्जा, रसद, डिजिटल और रचनात्मक अर्थव्यवस्था, इंजीनियरिंग और विनिर्माण व उद्योग में एआई के क्षेत्र में ' भविष्य के कार्य' की आवश्यकताओं के अनुरूप शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम भी अद्यतन किया जा रहा है। साथ ही, उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रमों की पहचान करने और उन्हें शामिल करने तथा शिक्षार्थियों की नियोजनीयता बढ़ाने के लिए अपनी पेशकशों का विस्तार करने हेतु स्वयम प्लस प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया है। एआईसीटीई ने पाठ्यक्रम संशोधन में शामिल उद्योग हितधारकों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, रोबोटिक्स, स्पेस टेक्नोलॉजी और वीएलएसआई डिजाइन जैसे उभरते क्षेत्रों में मॉडल पाठ्यक्रम तैयार करके इस दिशा में कई कदम उठाए हैं।

(घ): पीएम ई-विद्या के तहत, दीक्षा एक राष्ट्र, एक डिजिटल शिक्षा अवसंरचना है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दीक्षा में शामिल किया गया है। यह डिजिटल अवसंरचना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है और अत्यधिक विस्तारशील है। इस अवसंरचना का उपयोग सक्रिय पाठ्यपुस्तकें (ईटीबी) तैयार करने के लिए भी किया जा रहा है और वर्तमान में 7555 ईटीबी दीक्षा पर प्रकाशित की गई हैं। दीक्षा पर कुल 3.76 लाख ई-सामग्री उपलब्ध है और यह 128 भारतीय भाषाओं और 7 विदेशी भाषाओं में उपलब्ध है। कुल मिलाकर, विद्यार्थियों, शिक्षकों और अन्य हितधारकों द्वारा दीक्षा पर 564.05 करोड़ शिक्षण सत्र पूरे किए गए हैं।

नीति आयोग द्वारा अटल नवाचार मिशन (एआईएम) के तहत, एसटीईएम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित), रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और 3डी प्रिंटिंग को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स (एटीएल) स्थापित किए गए हैं।

(ङ): राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा जन्म या पृष्ठभूमि की परिस्थितियों के कारण अधिगम और उत्कृष्टता हासिल करने के अवसर से वंचित न हो। स्कूली शिक्षा में एनसीएफ-एसई 2023, एनसीएफ-एफएस 2022 और 'समग्र शिक्षा' योजना जैसी पहलें समावेशी शिक्षा, मूलभूत साक्षरता और कौशल विकास हेतु सहायता प्रदान करती है। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल में समावेशी कक्षाएँ, योग्यता-

आधारित शिक्षा, बहुभाषी शिक्षा और विविध अधिगम आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए सहायता संबंधी सामग्री शामिल है। सीडबल्यूएसएन को मुख्यधारा में लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडबल्यूडी) की सहकार्यता से दिव्यांगजन के उपकरण/सहायक उपकरण की खरीद/फिटिंग के लिए सहायता योजना (एडीआईपी योजना) को समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) के साथ समन्वय में लागू कर रहा है, ताकि सीडबल्यूएसएन को उपकरण/सहायक उपकरण वितरित किए जा सकें।

****